शोध मंथन Vol. XII No.IV Oct.-Dec. 2021 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

नैनीताल जनपद के बेतालघाट विकास खण्ड में कृषि की उत्पादकता का स्तर (खीरफ की फसल धान के विशेष सन्दर्भ में)

प्राप्तिः 30.10.2021
स्वीकृतः 26.12.2021

डा० ममता अधिकारी
अर्थशास्त्र विभाग
राजकीय महिला डिग्री कॉलेज
हल्द्वानी, नैनीताल

परिचय

भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला कृषि है। पिछले दो दशकों से अधिक अवधि में औद्योगिकीकरण के संगठित प्रयास के बावजूद कृषि का गौरवापूर्ण स्थान बना हुआ है। देश का सबसे बड़ा उद्योग होने के कारण कृषि देश की लगभग 65 प्रतिशत जनका की जीविका का स्त्रोत है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिये कृषि का विकास एक अनिवार्य शर्त है। आर. नर्कस का कहना है कि कृषि पर आधारित अतिरिक्त जनसंख्या को वहां से हटाकर नये आरम्भ किये गये उद्योगों में लगाया जाना चाहिए। नर्कस का मत यह है कि इसमें एक ओर कृषि उत्पादिता में वृद्धि होगी और दूसरी ओर श्रम शक्ति का उपयोग करके नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जा सकेगी। कृषि पैदावार में बढ़ोत्तरी रूकती गई उदाहरण के लिए 1950 से 1990 के बीच विश्व में खाद्यान्नों की पैदावार 2.2 फीसदी की दर से बढ़ी लेकिन 1990 से 2006 के बीच यह दर घटकर 1.3 फीसदी ही रह गयी। 1990–91 में भारत में अपनाये गये आर्थिक सुधार कार्यक्रमों तथा वैश्वीकरण के प्रभाव से हमारा कृषि क्षेत्र भी अछुता नहीं रहा जिसके कारण भारतीय किसानों का रूझान नगदी तथा व्यापारिक फसलों की ओर बढ़ने लगा। 1970–71 में चावल की खेती 23.02 प्रतिशत क्षेत्रफल में की गयी जिसमें चावल का उत्पादन 84.4 मिलियन टन रहा। सन् 1980–81, 1990–91, 2000–01 तथा 2007–08 में चावल की खेती क्रमशः 23.18 प्रतिशत, 23 प्रतिशत, 23. 82 प्रतिशत तथा 22.57 प्रतिशत क्षेत्रफल में की गयी जिसमें चावल का उत्पादन क्रमशः 107 मिलियन टन 149.4 मिलियन टन 170.9 मिलियन टन तथा 194.4 मिलियन टन रहा जो बताता है कि 1990–91 तथा 2007–08 की अवधि में चावल उत्पादन के क्षेत्रफल में गिरावट आने के बावजूद भी उत्पादन में वृद्धि देखी गयी।

कृषि के अतिरिक्त आय सृजन के विविध अंग होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से परिवृजित होकर अन्य क्षेत्रों से किया जाता है इसमें नौकरी, व्यापार, व्यवसाय और यातायात तथा विविध प्रकार के श्रमिकों के कार्य सम्मिलित हैं जो आंशिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि करते हैं इसलिये आय के स्त्रोत दो प्रकार के है एक गाँव के अन्तर्गत किया जाने वाला व्यवसाय इसलिए इसमें स्त्रियों का सहभाजन अधिक होता है दूसरा घर से बाहर जाकर अन्य समीप विकास खण्ड़ों में, कस्बों में या नगरों में जाकर श्रमिकों द्वारा कोई व्यवसाय करना। ग्रामीण व्यवसायों के अतिरिक्त रोजगार के कुछ अवसर विकास योजनाओं के माध्यम से शासन द्वारा प्रदत्त होते हैं जैसे मनरेगा योजना, इस प्रकार

ग्रामीण क्षेत्रों में आय व रोजगार के सृजन के राजकीय प्रयास तथा गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग रहता है फिर भी यह अनुभव होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी कम है और आय की मात्रा भी कम है, निचले जीवन स्तर पर जीने पर भी आय की मात्रा न्यूनतम रहती है यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि आखिर ग्रामीण स्तर पर आय वृद्धि के क्या स्त्रोत प्रदान किये जाये ताकि रोजगार के अवसर अधिक हों और विशेषतया मौसमी बेरोजगारी से निवृत्ति हो सके। नैनीताल जनपद के बेतालघाट विकास खण्ड में मुख्य व्यवसाय और संयोगी व्यवसाय में उत्पादकता के स्तर क्या हैं क्योंकि यह क्षेत्र प्रधानता कृषि आधारित है इसलिए कृषि की उतपादकता स्तर से ही समृद्धि के स्तर का निर्धारण हो सकता है।

शोध पूर्वावनलोकन

1. हैरीसन (1967–68) ने तमिलनाडू के तन्जौर जिले में धान पर शोध किया और वे इस परिणाम पे पहुंचे कि छोटे किसान की लागत और प्रतिफल दोनों कम हैं और यह भी बताया कि छोटे किसान प्रति हेक्टेयन भूमि पर भूमि, खाद, जुताई, मजदूरी पर ज्यादा खर्च करते हैं।

2. हनुमन्थःराव (1975) ने पंजाब राज्य में धान की संकर जाति पर अध्ययन किया और पाया कि सामान्य जाति काधान और हाइब्रिड धान के पैदावार और गुणवत्ता में काफी अन्तर है।

3. भट्टाचार्य और मिश्रा (1981) ने यह निष्कर्ष निकाला कि धान की पुष्पकुंज को भार और दानों की संख्या प्रत्येक पेनिकल में 22 जातियां धान की पाई गई।

4. डेंगे (1981) के अध्ययन में पौधे की ऊँचाई दानों की संख्या प्रत्येक पेनिकल, जोतने वालों की संख्या, प्रत्येक पौधे में दानों का भार, पुष्प की लम्बाई, प्रत्येक पौधे में पुष्पकुंज की संख्या कितनी है यह बताया।

5. शर्मा और रिचार्या (1995) के अध्ययन में बासमती चावल की किस्में, ज्यादा उत्पादन के लिये कौन–कौन सी उच्च तकनीकी का उपयोग किया गया है।

पूर्व में किये गये अध्ययन से पता चला कि किसी ने भी उत्तराखण्ड राज्य के नैनीताल जनपद में खरीफ की फसल धान के विषय में अध्ययन नहीं किया है। अतः मेरा शोध पत्र इस क्षेत्र से सम्बधित है।

उद्देश्य

- चयनित गांवों के किसानों की सामाजिक और आर्थिक संरचना का अध्ययन करना।
- चावल की खेती पर लगी लागत और प्रतिफल को ज्ञात करना।
- चावल की खेती की उत्पादकता को निर्धारित करने वाले तत्वों का अध्ययन करना।
- कृषि में प्रयुक्त तकनीकी का अध्ययन करना।
- कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन–कौन सी नीतियां अपनायी जा रही हैं। उनकी समीक्षा करना इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है।

परिकल्पना

- दो भिन्न गांवो के किसान की सामाजिक आर्थिक दशा एक समान है।
- भूमि की स्थिति भिन्न होने पर भी खेती की लागत में कोई अन्तर नहीं है।
- कृषि की उत्पादकता स्तर से ही समृद्धि के स्तर का निर्धारण होता है।
- खाद्यान्न फसलों की लागत अधिक और प्रतिफल कम है।

शोध प्रविधि

उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस अध्ययन के लिए अध्ययन विधि का निर्धारण किया गया। यह मूलतः सर्वेक्षण आधारित अध्ययन है किन्तु इसमें सूचना के मूलस्त्रोत तक पहुंचने के लिए द्वितीयक सूचना स्त्रोतों का उपयोग में लाना अपरिहार्य है इस कारण सर्वप्रथम सन्दर्भित क्षेत्र में विकास खण्ड के कार्यालयों से उपयोगी समंको का एकत्रीकरण किया जायेगा इस अध्ययन के लिए तीन स्तरों पर आंकड़े एकत्रित किये जायेंगे। प्रथम विकास खण्ड का चयन जो कि पूर्वनिर्धारित या जानबूझकर लिया गया है। दूसरा ग्राम अध्ययन के लिए न्यायदर्श तीन गांवों का चयन किया जायेगा। गांव का चयन सर्वप्रथम यातायात के साधन से दूरी के आधार पर किया जायेगा।

इस चयन में विविध फसलों के उत्पादन के आंकड़ों का तथा गांव की स्थिति का, उपलब्ध ा सिंचाई का और उत्पादित फसलों के विवरण का ध्यान रखा जायेगा। विशेषता के अनुसार प्रत्येक वर्ग में एक गांव का चयन इस ढंग से किया जायेगा कि हर विशेषता का प्रतिनिधित्व हो सके।

तीसरा किसानों का चयन करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि प्रत्येक किसान धान ज्यादा बोने वाले हो अर्थात सम्पन्न लोग हों जिनके जमीन अधिक हैं कृषि करने योग्य, इस प्रकार यह चयन तीन स्तरों पर स्टेटीफाइड सेम्पल द्वारा किया जायेगा। प्राथमिक सूचना संग्रहण करने के लिये दो प्रकार की अनुसूची तैयार की जायेगी। प्रथम व्यापक विषय विकासखण्ड सम्बन्धी सूचनायें, द्वितीय किसान की उपक्रम सम्बन्धी विशेष सूचनायें जिनमें व्यावसायिक कौशल और उत्पादकता स्तर निर्धारकों की जानकारी होगी।

तालिका 1.1 अध्ययन के लिये चयनित गाँव और किसान

क्र. सं.	विकास खण्ड	गाँव	किसानों की संख्या
1	बेतालघाट	1– रतौड़ा	10
		2– आमबाड़ी	10
		3– बर्धौ	10
			30 न्यादर्श किसान

अध्ययन की महत्ता एवं प्रस्तावित निष्कर्ष

यह तो सर्वविदित है कि उत्पादकता का स्तर ही किसी उपक्रम की श्रेष्ठता अथवा पिछड़ेपन का द्योतक होती है कृषि जगत में फसलों की उत्पादकता, दुग्धपालन एवं पशुपालन में उत्पादकता फलोत्पादन में उत्पादकाता इत्यादि का महत्व सर्वाधिक है जो समृद्धि का प्रतीक होता है। यह तकनीकी प्रगति का भी फलन है और मनोवृत्तिक आकांक्षाओं का भी फलन होता है। उत्पादकाता को जहां हम तकनीकी से समबद्ध कर सकते हैं वहीं यह मूलभूत अवरचनाओं की स्थापना से भी सम्बद्ध कर सकते हैं जहां अचरचना सुविस्तृत है यातायात के साधन विकसित भण्डार सुविधायें हैं और विपणन की सुविधायें दी गयी हैं वहां उत्पादित आय का स्तर ऊँचा होता है। इस अध्ययन के निम्न प्रस्तावित परिणाम हो सकते हैं–

- तकनीकी को अपनाने का स्तर भूमि की उपलब्धता पर आधारित पाया जायेगा।
- अध्ययन के दौरान यह पता चलेगा कि खरीफ की फसल चावल बेतालघाट की मुख्य फसलों में से एक है जो कि सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है।
- यह पता चला कि अध्ययन क्षेत्र में श्रमिक की मजदूरी अधिक है।
- धान को बोने से पकने तक आयी लागत और कुल धान की कीमत के बीच काफी कम अन्तर देखने को मिला।
- गाँव के सभी किसान संकर जाति के बीज बोने लगे हैं, मुख्यतया धान के लिये।

संदर्भ

1. दत्त रूद्र, सुन्दरम के.पी.एम., भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2015 नवीन संस्करण।
2. इकोनोमिक सर्वे, भारत सरकार।
3. मिश्र एस.के., पुरी वी.के., भारतीय अर्थव्यवस्था हिमालया पब्लिशिंग हाउस मुम्बई। संस्करण 2005
4. बारवाले आर., सिंह ए. (1997) rice reed in India.
5. Dhondhiyal S.P., (1991) Farm Management 'An Economic Analysis' Aman Publishing House.
6. Dant wales M.L., (1993) Economic of hybried rice cultivation in India.
7. Joshi G. R. (2006) Modern rice technology, income distribution and poverty in the tarai region of Nepal.
8. NSSO (1999-2000) Consumption survey repot.
9. Singh K., (1993) Economics of Hybried rice programme in Pubjab: Potentials and issues in: Barwale, B.R. ed Hybried rice: Food recurity in India, Madrass, Mechnillan Indian Limited.

संख्या
किसान